आतंकवाद और नक्सली हिंसा रहेगी अहम चुनौती

चुनौती

प्रभात कुमार राय

21 वीं सदी का प्रथम एक दशक व्यतीत हो गया। इसमें भारत ने समूचे विश्व के साथ अत्यंत नृशंस आतंकवाद के जख्मों को झेला। 1950 के दशक में सिर उठाने वाले नगा आतंकवाद का परचम झुक चुका है। उसके बागी नेता केंद्र के साथ समझौता वार्ता की टेबिल पर हैं। पुरी उम्मीद है कि इस दशक के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान ही नगा आतंकवाद का भी, मिजो आतंकवाद की तरह ही अंत हो जाएगा। 1979 से जरनैलसिंह भिंडरवाला के साए में उभरे आतंकवाद का खात्मा 1993 में हो गया था, किंतु अभी भी कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है। 2011 से शुरू हुए दशक में पंजाब में आतंकवाद के पुनः उदय के आसार कदाचित नहीं हैं, फिर भी गहन सतर्कता की दरकार है।

आतंकवाद के परचम तले एक ताकतवर चुनौती पूर्वोत्तर से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) के नाम से उभरी। उल्फा ने भारत से विखंडित कर असम को एक पृथक देश के तौर पर तशकील करने का संकल्प लिया। उल्फा ने 1986 से हिंसक कहर असम पर बरपाया है। उल्फा ने बंगालियों, बिहारियों को और यू.पी वालो को निशाना बनाया। उल्फा के भयावह आतंक को खत्म करने के भारतीय फौज को आपरेशन बजरंग और आपरेशन राइनो संचालित करना पडा.। उल्फा के सर्वोच्च राजनीतिक कमांडर अरविंद राजखोवा के आत्मसमर्पण के पश्चात और 30 दिसंबर 2010 को उसकी जेल से रिहाई के बाद, उल्फा के साथ बातचीत के द्वारा असम में आतंकवाद समस्या के समाधान की प्रबल संभावना सामने आई है। उल्फा का सैन्य कमांडर परेश बरुआ अभी सरकार के साथ किसी शांति वार्ता के मूड में नहीं दिखता। वही अब उल्फा आतंक के खात्मे की राह में एकमात्र रोडा है। आशा है कि कुछ देर से ही परेश बरुआ भी वार्ता की टेबिल पर आ जाएगा।

कश्मीर में 1988 से निरंतर बर्बर जेहादी आतंकवाद के हाथों हजारों जख्म झेल चुके और बर्बर जेहाद के हाथों एक लाख से अधिक जानें गवां चुके भारत को कुछ राहत का एहसास हुआ। वर्ष 2011 से प्रारम्भ हुए दशक में भी भारत के समक्ष बेहद बर्बर आतंकवादी जेहाद सबसे प्रमुख चुनौती के रुप में रुबरु रहेगा। समस्त अमेरिकी कूटनीतिक दबाव के बावजूद पाक अधिकृत कश्मीर में धर्मान्ध जेहादियों के सैकडों. आतंकवादी प्रशिक्षण कैंप संचालित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉंफ्रेंस का शाह जिलानी धडा अपनी पाकपरस्ती से बाज आने के लिए कदाचित तैयार नहीं है। जेहाद की खुले तौर पर हिमायत करने देशद्रोही तत्वों से पूर्णतः निपट लेने की कडी चुनौती भी राष्ट्र के सामने पेश रहेगी। कश्मीरी नौजवानों का दिल जीते बिना कश्मीर में जेहदी आतंकवाद को फैसलाकुन तौर पर पराजित करना नामुमकिन होगा।

इस दशक में नक्सल आतंकवाद दूसरी सबसे अहम चुनौती के तौर पर कायम रहेगा। 43 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के नक्सलबाडी इलाके से उभरा और कामरेड चारु मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में परवान चढा नक्सल किसान विद्रोह परंपरागत हथियारों से अपनी सफर शुरू करके, राष्ट्र के 22 राज्यों में विस्तारित होकर, ऑटोमैटिक मशीनगनों और राकेट लांचरों से लैस हो जाने तक का अपना आतंकवादी रास्ता तय कर चुका है। 43 साल पुरानी नक्सल बगावत को काबू

> 1979 से जरनैलसिंह भिंडरवाला के साए में उभरे आतंकवाद का खात्मा 1993 में हो गया था, किंतु अभी भी कुछ आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है। पंजाब में आतंकवाद के पुन: उदय के आसार कदाचित नहीं हैं, फिर भी सतर्कता की दरकार है।

करना कदाचित आसान नहीं होगा, क्योंकि वस्तुतः यह एक सामाजिक-आर्थिक मसला है, जिसकी जडों में देश के करोडों. किसानों का खासतौर पर आदिवासी किसानों का सामंती संस्कार समेटे पूँजीशाही व्यवस्था द्वारा जारी निर्मम नृशंस शोषण-उत्पीड़न नीहित रहा है। इस दशक में नक्सल तत्वों से निपटना काफी कठिन काम सिद्ध होगा।

प्रो-कॉरपोरेट सोच समझ वाले किसान विरोधी चिदंबरम सरीखे गृहमंत्री तो समूचे हालात को और अधिक बद से बदतर बना सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किसान समर्थक आर्थिक नीतियों का निर्माण और संजीदा तौर पर उनका निष्पादन ही देश को नक्सल आतंकवाद से निजात प्रदान कराने की राह तैयार कर सकते हैं। केवल सैन्य शक्ति के बलबूते पर नक्सल बगावत को कदापि कुचला नहीं जा सकता। नक्सल तत्वों के प्रभाव से यदि अत्यंत तेजी से किसानों को अलग थलग नहीं किया गया और विगत दशक की तर्ज पर ही किसान निरंतर ही नक्सल तत्वों के असर में जाते रहे तो वर्तमान दशक के अंत तक राष्ट्र, नक्सलों द्वारा उत्प्रेरित गृह युद्ध की चपेट में घिर सकता है।

(लेखक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है)

आतंकवाद

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author's permission